भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1639

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

मांगदेछू जल विद्युत परियोजना

1639. डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भूटान में जिस 720 मेगावाट मांगदेछू जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु द्विपक्षीय अंतर-सरकारी करार किया गया था और जो निर्माणाधीन थी, उस परियोजना ने विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारत और भूटान ने प्रथम भारत-भूटान संयुक्त उद्यम जल विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं; तथा यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) भारत और भूटान द्वारा उक्त परियोजना हेतु प्रदान की जाने वाली निधि के अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस परियोजना के माध्यम से उत्पादित अधिशेष विद्युत की भारत को आपूर्ति किए जाने की संभावना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना पर कार्य कब शुरू और पूरा किया जाएगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी हां, भूटान में 720 मेगावाट की मांगदेछू जल-विद्युत परियोजना वर्ष 2019-20 के दौरान शुरू की जा चुकी है और इससे विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है। परियोजना से उत्पादन निम्नानुसार है:

यूनिट-1 (180 मेगावाट) - 1414.02 एमयू
यूनिट-2 (180 मेगावाट) - 1190.18 एमयू
यूनिट-3 (180 मेगावाट) - 693.06 एमयू
यूनिट-4 (180 मेगावाट) - 1327.56 एमयू

2 फरवरी, 2021 तक संचयी उत्पादन 4624.82 एमयू है।

(ख) : दो सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से निम्नलिखित चार संयुक्त उद्यम (जेवी) जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए दिनांक 22.04.2014 को भूटान सरकार और भारत सरकार के एक अंतर सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए:

जेवी भागीदार	**परियोजना का नाम**
एसजेवीएन लिमिटेड (भारत सरकार का सीपीएसयू) और डीजीपीसी (भूटान सरकार का पीएसयू)	खोलोंग्छू एवं वांगछू जल-विद्युत परियोजनाएं
एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का सीपीएसयू) और डीजीपीसी (भूटान सरकार का पीएसयू)	चमखरछू -I जल-विद्युत परियोजना
टीएचडीसी (आई) लिमिटेड (भारत सरकार का सीपीएसयू) और डीजीपीसी (भूटान सरकार का पीएसयू)	बुनखा जलाशय जल-विद्युत परियोजना

उपर्युक्त में से, भूटान सरकार और खोलोंग्छू हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड (एसजेवीएन लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सीपीएसयू और डीजीपीसी (ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन), भूटान सरकार का पीएसयू) के बीच दिनांक 29.06.2020 को संयुक्त उद्यम (जेवी) मोड के कार्यान्वयन के लिए भूटान में 600 मेगावाट की खोलोंग्छू जल-विद्युत परियोजना के लिए रियायती करार किया गया था।

600 मेगावाट की खोलोंग्छू जल-विद्युत परियोजना उत्तर-पूर्वी भूटान में त्राशीयांगत्से जिले में खोलोंग्छू नदी पर स्थित रन-ऑफ-रिवर परियोजना है। इस परियोजना से 90% विश्वसनीय वर्ष में 2568.52 मिलियन यूनिट (एमयू) का उत्पादन होगा।

(ग) : संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) में एसजेवीएन और डीजीपीसी की समान शेयरधारिता (50:50) है। परियोजना को 70:30 के ऋण-इक्विटी अनुपात के तहत वित्तपोषित किया जाएगा। भारत सरकार संयुक्त उद्यम कंपनी में डीजीपीसी की इक्विटी के भाग अर्थात 15% अनुदान के रूप में प्रदान करेगी और 15% इक्विटी शेयर का योगदान एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा दिया जाएगा।

(घ) : जी हाँ, परियोजना के माध्यम से उत्पन्न अधिशेष बिजली की आपूर्ति संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा भारत को की जाएगी। संयुक्त उद्यम जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास के संबंध में दिनांक 22.04.2014 को भूटान सरकार और भारत सरकार के बीच अंतर सरकारी करार के अनुसार, परियोजना से बिक्री योग्य ऊर्जा का 12% (विद्युत संयंत्र सहायक खपत को घटाकर उत्पन्न ऊर्जा) परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के पहले 12 वर्षों के दौरान रॉयल्टी ऊर्जा के रूप में और उसके बाद रियायत अवधि की समाप्ति तक 18% विद्युत आरजीओबी को दी जानी है।

शेष ऊर्जा में से, रॉयल्टी ऊर्जा को घटाकर बिक्रीयोग्य ऊर्जा का 70% दीर्घावधि विद्युत खरीद करार रूट के तहत और शेष बाजार तंत्र के माध्यम से बेचा जाएगा। तथापि, आरजीओबी को बिक्री योग्य ऊर्जा पर इनकार करने का पहला अधिकार होगा और भूटान के उपयोग के लिए आवश्यक ऊर्जा से अतिरिक्त ऊर्जा को जेवी कंपनी द्वारा भारत में लाभार्थियों को बेचा जाएगा।

(ङ) : खोलोंग्छू जल-विद्युत परियोजना कार्यों को अवॉर्ड किए जाने से 59 महीनों की अवधि में शुरू किया जाना है। परियोजना की निर्माण-पूर्व गतिविधियां पूरी कर ली गई हैं।

****